वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (ग) यूरोपीय संघ श्रेणी के अंतर्गत परिधानों का कुछ प्रेषण दिसंबर, 1998 में यूरोपीय संघ पत्तनों पर रुकना शुरू हो गया था क्योंकि इन श्रेणियों के संबंध में 1998 के लिए वार्षिक स्तर अधिक हो गया था। उपलब्ध सूचना के अनुसार तीन श्रेणियों में रुके हुए प्रेषणों का अनुमानित मूल्य 40 करोड़ रु० है। ए ई पी सी के प्रतिनिधिमंडल को इस संबंध में यूरोप भेजा गया था। मामले को भारत द्वारा द्विपक्षीय तौर पर यूरोपीय आयोग तथा यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ उठाया भी गया था। इस बीच, नवीन 1999 कोटाओं को वापस भारत आने वाले किसी प्रेषणों के लिए जारी किया जा रहा है तथा हमारे सीमा शुल्क अधिकारियों ने यूरोप को पुनर्निर्यात करने के उद्देश्य से किसी ऐसे माल के त्वरित निकासी के लिए कदम उठाये हैं।

वस्त्र निर्यात उद्योग में मंदी

928. **श्री डी.पी. यादव:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश का परिधान निर्यात उद्योग भारी मंदी के दौर से गुजर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस उद्योग को मंदी से बचाने हेतु कोई कारगर कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (ग) देश में परिधान निर्यात उद्योग भारी मंदी के दौर से नहीं गुजर रहा है। तथापि, परिधानों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है जिनमें क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहन देना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत माल के आयात का अधिकार देना, निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात के लिए विशेष प्रबंध करना आदि शामिल हैं।

Development of sericulture sector in Madhya Pradesh

929. MISS MABEL REBELLO: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the amount of financial assistance provided for development of sericulture in Madhya Pradesh;

(b) the total amount spent on Kosa/Mulberry development under various schemes and share of SC/ST people benefitting from these schemes;

(c) the future plan being formulated for upliftment of Sericulturists and Kosa/Mulberry growers;

(d) whether it is a fact that after spending so much money on so many project, the quality and quantity of Kosa Silk is not improved; and

(e) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) and (b) The amount of financial assistance provided for development of sericulture [mulberry & tasar(Kosa)] in Madhya Pradesh during the VIII & IX plan are as under:—

(Rs. in crore)

Sector	VIII Plan (1992—97)	IX Plan (1997-98 upto Dec.98)
Mulberry	4.55	0.47
Non-mulberry	5.21	3.58
Total	9.76	4.05

The programmes implemented for tasar(Kosa) sericulture mainly benefit the tribal tasar silkworm rearers. The majority of the rearers/farmers being benefited from these programmes belong to SC/ST.

(c) In the IX plan period the Central Silk Board(CSB) has taken up implementation of Catalytic Development Schemes in collaboration with State Sericulture Department for development of sericulture. 16 projects sent by the State Sericulture Department have already been approved for implementation so far at a total cost of Rs.3.80 crore out of which CSB's share is Rs. 1.85 crore.